कृषि को मिले राहत

वर्ष 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद कृषि क्षेत्र के सामने चुनौतियां कई स्तरों पर बढ़ती गयीं. भले ही जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी सिमटती रही, लेकिन आज भी कृषि पर देश की आधी आबादी अपने रोटी-रोजगार के लिए निर्भर है. चुनावी साल में किसानों की चिंता और किसान संगठनों का प्रदर्शन जिस तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे वक्त में सरकार से इसके लिए लोकलुभावन बजट की उम्मीद स्वाभाविक ही है. सरकार किसानों को उर्वरक, बीज, यूरिया आदि पर सब्सिडी के माध्यम से राहत देती है. अब सभी प्रकार की सब्सिडी को मिला कर कैश के रूप में राहत देने का प्रावधान किया जा रहा है. अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो सरकार को सालाना इसके लिए 70 हजार करोड़ रुपये खर्च करने होंगे. हालांकि, चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा लक्ष्य के मुकाबले लगभग 115 प्रतिशत के स्तर को पार कर चुका है. ऐसे में अंतरिम बजट में राजकोषीय घाटा पूरा करने की चुनौती एक बड़ी चिंता होगी, लेकिन किसान मतदाताओं को नजरअंदाज करने का जोखिम सरकार कतई नहीं उठाना चाहेगी. ऐसे में उम्मीद है कि सरकार किसानों को राहत देने के लिए नये विकल्पों का इस्तेमाल कर सकती है. बीते बजट में सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य को उत्पादन लागत से 1.5 गुना करने का वादा की थी. हालांकि, इस प्रकार की लाभकारी योजनाओं का फायदा किसानों को तभी हो सकता है, जब वह अपने उत्पादों को उचित/ सरकारी चैनलों तक पहुंचा पाये. अमूमन, छोटे और मझोले किसान गांव में ही अपने उत्पादों को गैरवाजिब दामों पर बेच देते हैं, जिससे वे ऐसी योजनाओं के फायदे से वंचित रह जाते हैं और इसका फायदा बिचौलिये उठा लेते हैं. देश में छोटे कृषकों की संख्या 80 फीसदी से अधिक है और यही वर्ग कीमतों की बढ़ोतरी, आय में कमी और कर्ज के बोझ में दबे रहने को मजबूर है. कृषि उत्पादन से जुड़ी समस्याओं, मौसम की मार और कर्ज में दबे निराश किसान अक्सर आत्महत्या जैसा भयावह कदम उठा बैठते हैं. कृषि संकट से किसानों को उबारने के लिए तमाम राज्य सरकारें कर्ज माफी को अपना चुनावी मुद्दा बनाती हैं, लेकिन यह कोई ठोस समाधान नहीं है, यह नीति आयोग भी मानता है. अहम समस्या है कि कृषि संकट के जाल में फंसे ज्यादातर किसान संस्थागत ऋण तक नहीं पहुंच पाते. महाजनों के कर्ज के चंगुल में फंसने के बाद उनके लिए उबर पाना मुश्किल हो जाता है. बिचौलियों की धोखाधड़ी और महाजनों के कर्ज से किसानों को मुक्त कराने के लिए बड़े स्तर पर कृषि सुधार की पहल करनी होगी. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहन और रोजगारपरक नीतियां बनाकर स्थायी समाधान खोजने की कोशिश होनी चाहिए. साथ ही कॉरपोरेट को मिलनेवाली सब्सिडी और करों में राहत की तर्ज पर ग्रामीण उद्यमियों को भी प्रोत्साहित करने जैसे फैसले करने होंगे, तभी कृषि और किसानों का कल्याण हो सकेगा.

कृषि संकट से किसानों को उबारने के लिए तमाम राज्य सरकारें कर्ज माफी को अपना चुनावी मुद्दा बनाती हैं, लेकिन यह कोई ठोस समाधान नहीं है, यह नीति आयोग भी मानता है.

क्षेत्रीय दलों के छुपे पत्ते

नवीन जोशी
वरिष्ठ पत्रकार
naveengjoshi@gmail.com

न तो साल 2014 के आम चुनाव जैसी परिवर्तन की आकांक्षा जोर मार रही है, न ही सत्ता-विरोधी लहर दिख रही है. साल 2019 का लोकसभा चुनाव कई तरह की संभावनाएं ला सकता है. यदि भाजपा-नीत गठबंधन बहुमत पाता है या भाजपा और कांग्रेस में कोई दल सत्ता के करीब पहुंचता है, तो स्थितियां असामान्य नहीं कही जायेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो? अगर दोनों राष्ट्रीय पार्टियों में से कोई इतनी सीटें नहीं जीत सका कि विभिन्न क्षेत्रीय दल किसी एक को समर्थन देकर सरकार बनाने में मदद करें, तब? देश ऐसे चुनाव परिणाम पहले भी देख चुका है, जब क्षेत्रीय दलों के चुनावोपरांत गठबंधन की सरकार बनाने में राष्ट्रीय पार्टी बाहर से समर्थन देने को मजबूर हुई.

छोटे-छोटे दलों की 'खिचड़ी' सरकारें स्थिर नहीं होतीं, यह भी हम खूब देख चुके हैं. इसके बावजूद यह एक बड़ी संभावना बनी रहती है. क्षेत्रीय दलों के नेताओं के मन में एक बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने की महत्वाकांक्षा इसी कारण फलती-फूलती रही है. इस बार भी यह बहुत जोर मार रही हो, तो कोई आश्चर्य नहीं.

विरोधी दलों की कोलकाता रैली में इस पर सभी सहमत थे और पुरजोर कह रहे थे कि देश तथा लोकतंत्र को बचाने के लिए भाजपा को हराना आवश्यक है. इस उद्देश्य के प्रति सभी ने संकल्प भी व्यक्त किया, लेकिन ऐसी कोई राह नहीं निकाली कि वे भाजपा के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा या गठबंधन बना लेंगे. कोलकाता रैली के बाद फिर स्पष्ट हुआ है कि ज्यादातर क्षेत्रीय दल अपने-अपने राज्यों में भाजपा को शिकस्त देने की हरचंद कोशिश करेंगे. उनमें किसी भी तरह का गठबंधन चुनाव बाद ही होने के आसार हैं. तेलुगु देशम और एनसीपी जैसे चंद दल ही हैं, जो अपने-अपने राज्यों में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके भाजपा का मुकाबला करनेवाले हैं.

कहा जा सकता है कि इसके पीछे क्षेत्रीय क्षत्रपों की महत्वाकांक्षा ही है. उनकी नजर चुनाव बाद पैदा होनेवाली स्थितियों का अधिक से अधिक लाभ उठाने पर टिकी हुई है. इसलिए वे चुनाव-पूर्व किसी प्रतिबद्धता से बच रहे हैं.

सीटों के लिहाज से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में दो महत्वपूर्ण दलों- सपा और बसपा का गठबंधन हो चुका है. पिछले चुनाव नतीजों का सामान्य गणित, जो आवश्यक नहीं कि सही ही बैठे, कहता है कि इस गठबंधन से भाजपा को पचास सीटों तक का नुकसान हो सकता है. भाजपा के लिए यह बहुत बड़ा धक्का होगा. सपा-बसपा मानकर चलेंगे ही कि उनके पक्ष में इससे भी अच्छा परिणाम आयेगा. मान लिया कि सपा-बसपा को उत्तर प्रदेश में 50 सीटें मिल जाती हैं, तो क्या वह लोकसभा में एक बड़ी ताकत नहीं होगी? किसी राष्ट्रीय दल के बहुमत से काफी दूर रह जाने पर वह स्वयं सत्ता की दावेदार नहीं बनेगी?

समझा जा सकता है कि ममता बनर्जी की भाजपा विरोधी विपक्षी रैली को पूरा समर्थन देने के बावजूद मायावती स्वयं उसमें शामिल क्यों नहीं हुईं. उन्होंने अपना प्रतिनिधि भेजा. अखिलेश यादव वहां गये, क्योंकि अभी वे प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने के लिए काफी नये हैं. मायावती के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता.

इसी कारण ने राहुल गांधी को भी उस विशाल विपक्षी मंच से दूर रखा, हालांकि उनके एक से ज्यादा प्रतिनिधि वहां मौजूद थे. राहुल प्रधानमंत्री पद के स्वाभाविक दावेदार माने जाते हैं.

ममता बनर्जी हाल के महीनों में भाजपा-विरोधी क्षेत्रीय नेताओं की अग्रिम पंक्ति में रही हैं. कोलकाता रैली का आयोजन उन्होंने बंगाल में वामपंथियों के मुकाबले भाजपा-विरोध की अपनी शक्ति दिखाने के लिए ही नहीं, राष्ट्रीय फलक पर अपनी धमक जताने के लिए भी किया. वर्तमान लोकसभा में विपक्ष में कांग्रेस के बाद तृणमूल कांग्रेस सबसे बड़ा दल है. तो वे अपने दांव क्यों नहीं चलेंगी? ऐसी स्थितियां भी तो बन सकती हैं, जब क्षेत्रीय क्षत्रपों को नेतृत्व के लिए उनके नाम पर राजी होना पड़े. देवगौड़ा या इंद्र कुमार गुजराल की तुलना में ममता बनर्जी कहीं ज्यादा परिचित और सक्रिय नाम नहीं हैं क्या? मायावती और ममता में चुनाव करना पड़े, तो अन्य क्षेत्रीय दल किसके पक्ष में खड़े होंगे?

कांग्रेस तीन राज्यों में सत्ता में वापस अवश्य आ गयी है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के मुकाबले अकेली पार्टी होने के बावजूद उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है. कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में उसने बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल जैसे बड़े राज्यों में उसके पैर उखड़े हुए हैं. उत्तर-पूर्व में उसका सफाया है. पिछले लोकसभा चुनाव में वह मात्र 44 सीटों पर सिमट गयी थी. इस बार आखिर उसे कितना फायदा हो जायेगा? कुछ अजूबा घटित हो तो नहीं कह सकते, वर्ना सौ-सवा सौ सीटें पाना उसके लिए बड़ी उपलब्धि होगी.

भाजपा दो सौ के आंकड़े से नीचे रह जाये, तो भी कांग्रेस सत्ता की दावेदारी कैसे कर सकेगी? स्वाभाविक है कि वह भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए क्षेत्रीय दलों को समर्थन देगी. यह बड़ा कारण है कि क्षेत्रीय दल फिलहाल कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं. उलटे, वे कांग्रेस से स्वयं समर्थन की आशा लगा रहे हैं. सपा-बसपा ने कांग्रेस को गठबंधन में शामिल नहीं करने के बावजूद सोनिया और राहुल की सीटों पर चुनाव नहीं लड़ने का फैसला क्या यूं ही किया है?

आसन्न आम चुनाव के परिणामों की ऐसी संभावनाएं क्षेत्रीय दलों की महत्वाकांक्षाओं को हवा दे रही हैं. इसलिए आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि भाजपा के विरुद्ध एक मंच पर इतनी बड़ी जुटान होने के बावजूद महागठबंधन की संभावना दूर-दूर तक नहीं दिख रही. ये क्षेत्रीय दल भाजपा को हराना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए अपने राजनीतिक हितों की तिलांजलि नहीं दे सकते. भाजपा को परास्त करने की रणनीति के साथ-साथ उन्हें अपने लिए अधिकतम संभावनाओं के द्वार खोले रखने हैं.

यह विरोधाभास आज की चुनावी राजनीति का सत्य है. सत्य यह भी है कि इसमें राजनीतिक अस्थिरता, उठा-पटक और जल्दी-जल्दी चुनाव के खतरे शामिल हैं. जनता का बड़ा वर्ग मोटे तौर पर अस्थिरता और अवसरवादी राजनीति को पसंद नहीं करता, लेकिन जातीय-धार्मिक-क्षेत्रीय गोलबंदियों से प्रभावित मतदान ऐसी स्थितियां ले ही आता है. ऐसी संभावना भांप कर ही भाजपा नेता अब जनता को 'खिचड़ी', 'स्वार्थी' और 'अस्थिर सरकारों' से आगाह करने में लग गये हैं. यानी, सभी दल अपने कुछ पत्ते छुपा कर खेल रहे हैं.

क्षेत्रीय दल भाजपा को हराना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए अपने राजनीतिक हितों की तिलांजलि नहीं दे सकते. भाजपा को परास्त करने की रणनीति के साथ-साथ उन्हें अपने लिए अधिकतम संभावनाओं के द्वार खोले रखने हैं.

संभावनाओं से भरा एक संबंध

डॉ नेहा सिन्हा
एसोसिएट फेलो, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन
nsinha.rnc@gmail.com

भारत तथा दक्षिण अफ्रीका के पारस्परिक संबंधों की जड़ें इतिहास की गहराइयों तक फैली हुई हैं. चूंकि दोनों देशों की कहानियां कई उतार-चढ़ावों से होकर गुजरी हैं, इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि इन दोनों देशों के संबंध स्नेह और सहानुभूति से सहेजे जायें, ताकि दोनों के बीच का बंधन और भी प्रगाढ़ हो सके. हालांकि, आधुनिक युग एवं खासकर वर्तमान कालखंड में इन दोनों के बीच का जुड़ाव तेजी से परवान चढ़ा है, जिसमें इस तथ्य का एक बड़ा योगदान है कि प्रधानमंत्री पद पर आने के पश्चात नरेंद्र मोदी दो बार दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर चुके हैं.

चूंकि पूरा विश्व इस वर्ष महात्मा गांधी के जन्म की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है, इसलिए दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर नयी दिल्ली में होनेवाले मुख्य राजकीय समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में सुशोभित करने का उन्हें दिया गया आमंत्रण स्वीकार कर लिया. पिछले वर्ष के अंत में अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में संपन्न जी20 शिखर सम्मेलन में जब दोनों नेता मिले, तो उन्होंने मोदी को अपनी इस स्वीकृति की सूचना दी. वैसे इस अवसर पर मुख्य अतिथि बनने हेतु पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आमंत्रित किया गया था, पर उन्होंने व्यस्तताओं की वजह से इसे स्वीकारने में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी. यह भी बताया गया है कि राष्ट्रपति रामफोसा ने वाराणसी में चल रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन में भी सहभागी होना स्वीकार किया है. प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आने की स्मृति में और विदेशों में बसे प्रवासी भारतीयों के योगदान का जश्न मनाने हेतु किया जाता है.

राष्ट्रपति रामफोसा दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा के त्यागपत्र देने के बाद सत्ता में आये थे, जिसके पश्चात वहां घोटालों तथा कुशासन के एक युग का अंत संभव हो सका, क्योंकि जुमा प्रशासन पर भ्रष्टाचार, धन शोधन तथा रिश्वतखोरी के कई आरोप लगे थे. भारत और अफ्रीका के संबंध सदियों पीछे प्रारंभ हुए और भारत ने रंगभेद के विरुद्ध उसके लंबे आंदोलन में भी उसका साथ दिया. आज दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के लगभग 15 लाख लोग निवास करते हैं, जो वहां की जनसंख्या का लगभग 3 प्रतिशत है. दोनों देश आपस में तो अत्यंत निकट तथा सद्भावपूर्ण द्विपक्षीय संबंध साझा करते ही हैं, यह संबंध कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों की साझी सदस्यता तथा उनमें दोनों के सक्रिय सहयोग तक भी विस्तृत है. इसके उदाहरण में आइबीएसए (भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका) एवं ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका) जैसे संगठनों को लिया जा सकता है. वर्ष 2018 में ब्रिक्स का दसवां शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में ही आयोजित हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने शिरकत की. इस सम्मेलन में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में शांति तथा प्रगति हेतु भारत की प्रतिबद्धता दोहराते हुए दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर बल दिया था. दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से एक डाक टिकट भी जारी किया, जिसे गांधी एवं मंडेला की विरासत के सम्मान में निकाला गया था.

इसके पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की थी, जहां उन्होंने आठ समझौतों को अंतिम रूप देते हुए सूचना संचार प्रौद्योगिकी, पर्यटन, खेल, संस्कृति, आधारभूत नवोन्मेष, नवीकरणीय ऊर्जा, दृश्य-श्रव्य तथा वीजा सरलीकरण प्रक्रिया के क्षेत्रों में परस्पर सहयोग के विस्तारीकरण की शुरुआत की थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका को 'मदीबा (नेल्सन मंडेला) के देश' तथा 'महात्मा गांधी की कर्मभूमि' की संज्ञा दी. इस अवसर पर उन्होंने भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया और यह भी उजागर किया कि पिछले दस वर्षों में दोनों राष्ट्रों के बीच उभयपक्षीय व्यापार में 300 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो स्पष्ट तौर पर दक्षिण अफ्रीका में भारत की तीव्र व्यापारिक दिलचस्पी का संकेत करती है.

अब राष्ट्रपति रामफोसा द्वारा भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में प्रतिभागिता स्वीकार करने से दक्षिण अफ्रीका के साथ हमारे संबंधों के पहले से भी ज्यादा मजबूत बनने की आशाएं उज्ज्वल हो गयी हैं. दोनों देशों के लिए यह एक और ऐसा मौका है, जब वे कई अतिरिक्त क्षेत्रों में सहयोग के संबंध में विचार-विमर्श कर सकते हैं. रामफोसा द्वारा स्वास्थ्य, कौशल विकास तथा डिजिटल क्षेत्रों को उन प्राथमिकताओं के अंतर्गत रखा गया है, जिनमें वे भारत के साथ संबंध बढ़ाना चाहते हैं. रामफोसा नयी दिल्ली में भारतीय कारोबारी समुदाय से भी इस मुद्दे पर विचार-विमर्श हेतु मिलेंगे कि भारत किस तरह दक्षिण अफ्रीका के सहयोग से अफ्रीका के अन्य देशों से भी अपने व्यापारिक संबंधों का संचालन तथा उनका विकास कर सकता है.

हम यह आशा कर सकते हैं कि राष्ट्रपति रामफोसा की भारत यात्रा दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत के संबंधों को और भी अधिक गहराई देते हुए दोनों देशों के लिए फलप्रद होगी, क्योंकि इस साझेदारी में अपार संभावनाएं छिपी हैं. यह अवसर दोनों देशों के बीच कारोबार के साथ ही दोनों देशों की जनता के बीच के संबंधों की बढ़ोतरी के लिए भी स्वर्णिम सिद्ध हो सकेगा.

(अनुवादः विजय नंदन)

राष्ट्रपति रामफोसा द्वारा भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में प्रतिभागिता स्वीकार करने से दक्षिण अफ्रीका के साथ हमारे संबंधों के पहले से भी ज्यादा मजबूत बनने की आशाएं उज्ज्वल हो गयी हैं.

बोधि वृक्ष

समाधान

दुनिया के धर्मों ने समस्याएं समाप्त नहीं की, बल्कि नयी समस्याएं खड़ी कर दी हैं. अगर दुनिया से धर्म समाप्त हो जाये, तो मनुष्य की पचास प्रतिशत समस्याएं उनके साथ चली जायेंगी. उसकी लड़ाइयां, उसके विरोध, उसके संघर्ष, उसकी दीवारें, उसके मंदिर-मस्जिद, उसके शास्त्र, उसके पंडित, उसके साधु, यह सारा उपद्रव विलीन हो जायेगा. लेकिन बुनियादी बात है कि क्या हम समाधान खोजते हैं, या समस्या खोजते हैं? अगर हम समाधान खोजते हैं, तो हम समस्या से पलायन खोज रहे हैं. एक आदमी के भीतर हिंसा होती है, तो चित्त में क्रोध होता है. हिंसा किसी को सुख नहीं दे सकती, क्रोध किसी को शांति नहीं दे सकता, द्वेष किसी के मन में संगीत नहीं ला सकता. इससे परेशान होकर वह समाधान खोजने जाता है. कोई कहता है, अहिंसक हो जाओ, तो समाधान हो जायेगा. यह वैसे ही है जैसे एक बीमार आदमी कहीं जाये और कहे कि मैं बीमारी से बहुत परेशान हूं और एक डॉक्टर उससे कहे कि तुम स्वस्थ हो जाओ, तो ठीक हो जायेगा. तो यह कितना पागलपन मालूम होगा! कोई डॉक्टर यह नहीं कहता. लेकिन धर्म के डॉक्टर यही कहते हैं- अगर हिंसा है, अहिंसक हो जाओ, सब ठीक हो जायेगा. बीमारी क्या है, कहां है, क्यों है, डॉक्टर उसको खोजता है और उसे दूर करने के उपाय खोजता है. अब बीमारी नहीं रह जाती, तो स्वास्थ्य उपलब्ध हो जाता है. इसी तरह जब हिंसा नहीं रह जाती, तो अहिंसा अपने-आप उपलब्ध होती है. लेकिन हमारे भीतर हिंसा होती है, पर हम अहिंसा में उपाय खोजते हैं. हमारे भीतर क्रोध होता है, हम क्षमा में उपाय खोजते हैं. हमारे भीतर लोभ होता है, तो हम त्याग में उपाय खोजते हैं. जो आदमी लोभी है, उसके त्याग के पीछे कोई न कोई लोभ काम करता है- स्वर्ग पाने का लोभ, मोक्ष पाने का लोभ, परमात्मा को पाने का लोभ. लेकिन लोभी आदमी के न्याय के पीछे लोभ मौजूद होगा. लोभी त्याग कैसे कर सकता है? वह तो जो भी करेगा, उसके पीछे लोभ होगा. इसलिए दुनिया में बहुत-से लोभी त्यागी हो जाते हैं.

आचार्य रजनीश ओशो

आपके पत्र

विपक्ष की चुनौती

इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष के लिए विधानसभा चुनावों के मुकाबले अलग तरह की चुनौतियां होंगी. विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं और लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर. इसके अलावा विपक्ष के पास नरेंद्र मोदी जैसा भी कोई चेहरा नहीं, जो सबको लुभा सके. यदि लोकसभा चुनाव को मोदी बनाम राहुल की जंग के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है, तो लगता नहीं कि मोदी का विजय-रथ रुकेगा. फिर मोदी इस वक्त सत्ता में भी हैं और वह मतदाताओं के लिए अनेक तरह की सौगातें लुटाते हुए उन्हें अपने पक्ष में कर सकते हैं. गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण की हालिया पहल भले ही न्याय के कठघरे में पहुंच कर लड़खड़ा जाए, लेकिन तब तक चुनाव निबट चुके होंगे. लिहाजा विपक्ष की चुनौतियां बड़ी हैं. देखना होगा कि इससे निबटने के लिए उनकी रणनीति क्या होती है?

डॉ हेमंत कुमार, गोराडीह, भागलपुर

इवीएम पर शक

बड़े आश्चर्य और दुर्भाग्य की बात है कि लोकसभा चुनाव सिर पर हैं और इवीएम पर फिर उंगलियां उठ रही हैं. अब लंदन में एक भारतवंशी अमेरिकी सैयद शुजा ने इसे हैक करने का गंभीर आरोप लगाया है. अब सरकार और चुनाव आयोग का यह दायित्व है कि वे जल्द दूध-का-दूध और पानी-का-पानी करें, ताकि देश की जनता के सामने सच्चाई आ सके. विपक्ष तो पहले ही इवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने पर अड़ा है. ऐसे में सरकार और चुनाव आयोग के लिए यह एक नयी चुनौती है, जिसमें उसे देश को संतुष्ट करना.

वेद मामूरपुर, नरेला

अहम है यह रिपोर्ट

प्रोफेसर मार्शल ने एक बार कहा था, मुद्रा वह धुरी है, जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है. आज हर कोई मुद्रा के पीछे भाग रहा है, जबकि सच्चाई यही है कि जो गरीब हैं, उनसे मुद्रा खुद भागता है. ऑक्सफेम की रिपोर्ट से यही सच एक बार फिर सामने आया. अमीर और अमीर तथा गरीब और गरीब हो गये. चाहे एशिया हो या यूरोप, अफ्रीका हो या अमेरिका, सब की एक ही कहानी है. भारत के अरबपतियों की संपत्ति में पिछले साल हर दिन 2200 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ, जबकि आजादी के बाद से ही तमाम लेखों, नेताओं के भाषणों एवं नीति निर्माताओं के दावों में यही कहा जाता रहा है कि गरीबी अब खत्म हुई कि तब खत्म हुई, मगर सच यही है कि गरीबों की आबादी लगातार बढ़ रही है. देश ने हर विचारधारा के शासकों को देख लिया. नेता गला फाड़-फाड़ कर गरीबों के जीवन स्तर को सुधारने के दाव करते रहे हैं, मगर सत्ता के पावर का लाभ अमीरों को ही मिलता रहा. यह ठीक है कि उनके पास उद्यमशीलता, पैसा, जोखिम उठाने की शक्ति है, मगर सच यह भी है कि सत्ता की जो मदद इन्हें मिलती रही है, वह गरीबी उन्मूलन के संकल्पों के प्रतिकूल ही रही है.

जंग बहादुर सिंह, गोलपहाड़ी, जमशेदपुर

कुछ अलग

जीवंत बने रहिए

कविता विकास
लेखिका
kavitavikas28@gmail.com

बीता हुआ समय बहुत कुछ सिखा जाता है. समय के साथ चलनेवाले खुश हैं कि उन्होंने अपनी मंजिल पाने के लिए सही कदम उठाया. मुसीबत तब होती है, जब हम समय से आगे निकलने की कोशिश में अवसाद के शिकार हो जाते हैं. समय बलवान होता है. समय अगर जख्म देता है, तो मरहम भी देता है. जाड़े के बाद गरमी ही आयेगी. चाहे लाख बारिश का इंतजार हो, आयेगी वह गरमी के बाद ही. फसल पकने का समय है, फूल खिलने का भी और जिंदा रहने का भी. समय से पहले न कुछ मिला है और न मिलेगा.

आज मनुष्य बहुत व्यस्त हो गया है. जेहन में ज्यादा से ज्यादा जानकारी भर लेने की कवायद उसे वक्त से पहले ही बूढ़ा बना रही है. आगे निकलने की होड़ में न तो वह अपने स्वाभाविक विकास पर ध्यान दे पाता है और ना उस वक्त से जुड़ी खुशियों का आनंद ले पाता है. ठंड में ब्लोअर की गरमी का एहसास करनेवाले क्या जानें सर्दी की गुनगुनी धूप का एहसास क्या होता है. छोटे-छोटे फ्लैट्स की गजभर बालकनी से जिसने ढलती शाम या उगते सूरज की लालिमा को आंखों में नहीं बसाया, वह कैसे जानेगा कि मौसमी फल-फूल से लदी बगिया सुकून-चैन का पर्याय होती है.

समय के साथ परिवर्तन आवश्यक है, परंतु भरसक कोशिश होनी चाहिए कि यह परिवर्तन प्रकृति के सान्निध्य में उससे सामंजस्य बनाकर हो. बहुत सारे रोगों का कारण ही प्रकृति से दूर हो जाना है. तेजी से जीवन का हर जंग जीतने की कोशिश में पड़ाव भी जरूरी है और हार बर्दाश्त करने की क्षमता भी. सांसों की एक लय है. न ज्यादा तेज, न ज्यादा धीमी. शरीर को स्वस्थ रखने के लिए यही गति चाहिए. जिंदगी कोई रेस नहीं है. हर व्यक्ति खास है, हरेक के पास अलग-अलग हुनर हैं. कोई गीत-नृत्य में पारंगत है, तो कोई खेल-कूद में. कोई पढ़ाई में, तो कोई घर संवारने में.

टीवी रियलिटी शो ने बच्चों को कम उम्र में प्रसिद्धि तो दिलायी है, पर उनका बचपन छीन लिया है. किसी भी क्षेत्र में अव्वल आने के लिए शारीरिक क्षमता से अधिक किया गया प्रयास हमेशा बुरे परिणाम ही लाता है. असफल होने का डर अलग मनोवैज्ञानिक दबाव डालता है. इसलिए ऐसे किसी काम में स्वयं को ना झोंकिए, जो प्रकृति के विरुद्ध है. अगर आपकी प्रकृति शांत रहने की है, तो शांत भाव से ही आगे बढ़ें.

अपने स्वाभाविक लय में जीने का अलग ही सुख है. यह दिमाग को शांत रखता है, जिससे जिंदगी का सुख जुड़ा हुआ है. अगर आपने अब तक केवल दूसरों की बुराइयां गिनने में समय गुजारा है, तो अब स्वयं में बदलाव लायें. यह कठिन नहीं है, बस केवल आत्मानुशासन की जरूरत है. एक लंबे अंतराल के बाद पता चलता है कि हमने जिंदगी उस काम में गुजार दी, जिसमें खुद अपना ही अहित हुआ. तो आनेवाले समय में इस बात का ख्याल रहे कि अच्छे और नेक काम में समय बीते. यही जिंदगी का फलसफा है. जीवन का मजा जीवंत रहने में है, इसलिए अपने स्वभाव के अनुसार जीवंत बने रहिए.

देश दुनिया से

जापान में मेट्रो ट्रेन में सुबह का नाश्ता मुफ्त!

दफ्तर जाने के पीक टाइम में सार्वजनिक परिवहन में बहुत भीड़ होना कोई नयी बात नहीं है. लेकिन जापान में इस समस्या से निबटने के लिए लोगों को खाने का लोभ दिया जा रहा है. सुबह आठ से नौ बजे तक जापान की राजधानी टोक्यो में मेट्रो भरी होती है. जापान की भीड़ बदनाम है. इस समय भीड़ को कम करने के लिए जापान मेट्रो ने सुबह और पहले निकलनेवाले यात्रियों को मुफ्त नाश्ते का ऑफर दिया है. अगर दो हजार यात्री इस ऑफर को लेने के लिए तैयार होते हैं, तो उन्हें मुफ्त टेम्पुरा दिया जायेगा. यह तला हुआ खाद्य पदार्थ है. यदि ढाई हजार यात्री सुबह जल्दी ट्रेन लेने को तैयार हो जाते हैं, तो उन्हें मुफ्त में सोबा नूडल वाली डिश दी जायेगी. और यदि तीन हजार लोग सुबह उससे भी जल्दी ट्रेन लेने को तैयार हो जाते हैं, तो उन्हें टेम्पुरा और सोबा दोनों ही मिलेंगे. गौरतलब है कि दुनिया के सबसे बड़े मेट्रोपोलिटन इलाके की मेट्रो चोजाई लाइन पर भीड़ कम करने की कोशिश कर रही है. वहां के परिवहन मंत्रालय के अनुसार, कीबा से मोंजेनाकाचो स्टेशनों के बीच सुबह पौने आठ से पौने नौ बजे तक 76,000 लोगों ने तोजाई लाइन का इस्तेमाल किया. इस समय ट्रेन में इतनी भीड़ होती है कि यात्री हिल भी नहीं सकते.

कार्टून कोना

साभार : बीबीसी

पोस्ट करें : प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001, **फैक्स करें** : 0651-2544006,
मेल करें : eletter@prabhatkhabar.in पर ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है